कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/24598/2017/10-11/ 1492 भोपाल, दिनांक 06-05-2021

प्रति,

श्री ब्रिजेन्द्र स्वरूप
वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003

विषयः– **Proposal for diversion of 201.079 hectares of forest land for Tawa —II underground coal mining in favour of M/ s. Western Coal Fields Limited, Pathakhera in Baitul District State of Madhya Pradesh.**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 8-52/2017-FC दिनांक 14/05/2019

––0––

प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक/8-52/2018-FC दिनांक 14/05/2019 से प्रदत्त प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन वन मंडल अधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा पत्र दिनांक 16/04/2021 से प्रस्तुत किया गया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

<table>
<tr><th>शर्त संख्या</th><th>शर्त</th><th>पालन प्रतिवेदन</th></tr>
<tr><td>(i)</td><td>Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged;</td><td>आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>Application for diversion of remaining forest land of 520 ha in the project (318.921 ha) be submitted by WCL for consideration;</td><td>रकबा 520.00 हे. का Breakup इस प्रकार हैः–
<table>
<tr><td>वनभूमि</td><td>396.279 हे</td><td>(i) 195.20 हे. वन स्वीकृति प्राप्त क्र. 8-97/97-FC दि. 22/01/199 तथा पत्र क्र. 5/29/97 /10/3 दि. 09.08.1999 (12.708 हे. सरफेस राइट) 195.20 हे. का ही भाग है।
(ii) 201.079 हे वन भूमि का प्रस्ताव अंतिम चरण स्वीकृति हेतु प्रचलित है।</td></tr>
<tr><td>शासकीय भूमि</td><td>54.456 हे.</td><td>–</td></tr>
<tr><td>निजी भूमि</td><td>69.265 हे.</td><td>–</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>520.00 हे.</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		कुल वनभूमि 396.279 हे. जिसमें से 195.20 हे. के लिए वन स्वीकृति आवेदक संस्था द्वारा प्राप्त कर ली गई है। शेष वनभूमि 201.079 हे. के लिए वनभूमि का स्वीकृति का प्रस्ताव आवेदन किया गया, इस वनभूमि पर आवेदक संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है इस प्रकार आवेदक संस्था द्वारा कोई उलघंन नहीं किया गया है। आवेदक संस्था द्वारा इस शर्त में संशोधन हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया है।
(iii)	Action is required to be initiated against the authorities in WCL in accordance with the section 3(A) and 3(B) of the Forest Conservation Act, 1980 against the officials who violated the provisions of FC Act 1980. State Government may also initiate legal action under Indian Forest Act 1927 for violation of their relevant law;	शर्त संख्या (ii) पालन प्रतिवेदन अनुसार
(iv)	The Regional office, Bhopal shall visit the underground mining project and report the status of the forest clearance and the on-going mining activities without valid Forest clearance under section 2(ii) of the FC Act along with the Nodal officer, Forest Conservation, Madhya Pradesh Forest Department. WCL will provide the copy of FC granted in past along with the details of the mining area of Tawa-II underground mining project over 520 ha which as per the EC report is forest land;	इस शर्त के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना है।
(v)	The Regional Office Bhopal should investigate along with the concerned officers of the forest department and WCL the status of entire Patherkhera coal block in Madhya Pradesh, the extent of forest land and the status of forest clearances in all such cases and submit comprehensive report on Forest clearance;	इस शर्त के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रतिवेदन दिया जाना है।

(vi)	WCL will deposit the NPV for the entire 520 ha immediately since the forest land has been used by the WCL in Tawa-II underground project in contravention of the FC Act.;	आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तावित रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि की एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 6,29,37,727/– भारत सरकार के एडहॉक कैम्पा मद में वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा किया गया है। आनलाईन जमा राशि की रसीद संलग्न है।
(vii)	WCL should submit the compliance report of in principle approval granted by this Ministry's letter F. No. 8-102/2004-FC dated 30.01.2012, in favour of WCL for diversion of another parcel of 90.00 ha of forest land, after expiry of the Forest clearance in 2003 and deposit the compensatory levies of Rs 255462766/- With interest of 12% per annum;	आवेदक संस्था द्वारा एक अन्य स्वीकृत शोभापुर खदान रकबा 90.00 हे. वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में सामान्य क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये 6,46,96,050/– भारत के कैम्पा मद में दिनांक 02/06/2018 को जमा की गई है। तथा राशि रूपये 64,69,605/– वन मंडल उत्तर बैतूल में डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से 04/06/2018 को जमा किया गया है। तथा पॉच गुना दाण्डिक क्षतिपूर्ति वनीकरण (90x5) = 450.00 Ha. की कुल राशि रूपये 16,75,42,827/– दिनांक भारत सरकार के कैम्पा मद में दिनांक 2/06/2018 को जमा की गई है तथा पर्यवेक्षण शुल्क की राशि रूपये 1,67,54,284/– वन मंडल उत्तर बैतूल के अकाउण्ट में ई– चालान द्वारा दिनांक 04/06/2018 को जमा किये गये है।
(viii)	The State Government will undertake study on impact of mining on wildlife especially tiger habitat in the entire project area and prepare the wildlife management plan for the entire reserve forest and the same will be implemented from the funds provided by the WCL. The clearance from NBWL may also be obtained because the area is populated by tigers in the surrounding tiger reserves;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण वन्यप्राणियों पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा।
(ix)	Penalty will be imposed as per the existing guidelines dated 29th January 2018;	शर्त संख्या (ii) पालन प्रतिवेदन अनुसार
(x)	Complete compliance of Forest Right Act 2006 in accordance with Ministry's guideline dated 03.08.2009 read with 05.07.2013 will be done by the State Government and submitted along with the compliance report;	आवेदक संस्था द्वारा अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत व निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कलेक्टर बैतूल द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा ग्राम सभा भोगईखापा जनपद पंचायत घोड़ाडोगरी जिला बैतूल का सहमति पत्र दिनांक 26/01/2011 प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है।

(xi)	The in-principle approval will be for the ex-facto regularisation of the violation committed by the Western Coalfield Limited for diversion of the forest land over the forest land 201.079 ha of forest land already broken with penal NPV and penal CA for 50 years (30yrs+20yrs)w.e.f. 25.10.1980. Further the in-principle approval will be effective after the payment of NPV and other outstanding dues with WCL in CAMPA account,	शर्त संख्या (ii) पालन प्रतिवेदन अनुसार
(xii)	The User Agency shall transfer online, the Net Present Value (NPV) of the forest land being diverted under this proposal, as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No. 202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No. 5-3/2007-FC dated 05.02.2009. The requisite funds shall be transferred through online portal into Ad-hoc CAMPA account of the State Concerned;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xiii)	The User Agency shall pay the additional amount of NPV, if so determined, as per the final decision of the Hon'b1e Supreme Court of India;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xiv)	The user agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank online only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage- I clearance;	आवेदक संस्था द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तावित रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि की एन.पी.व्ही. की राशि रूपये 6,29,37,727/– भारत सरकार के एडहॉक कैम्पा मद में वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा किया गया है। आनलाईन जमा राशि की रसीद संलग्न है।

(xv)	Period of diversion of the said forest land under this approval shall be for a period co-terminus with the period of the mining lease proposed to be granted under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and the Rules framed there-under, subject to a maximum period of 30 years. The State Government will submit the lease agreement document specified in the lease agreement;	आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार, कोल मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 43015/28/2017-LAIR(Vol.II) दिनांक 11/12/2019 का संदर्भ देते हुये लेख किया है कि वनभूमि Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण किया गया है इसमें अवधि निर्धारित नहीं होती है। अपितु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रकरण में द्वितीय चरण स्वीकृति जारी होने के दिनांक से खदान की अवधि 30 वर्ष की उन्हें मान्य है।
(xvi)	Area on surface of the mining lease shall be fenced and afforested;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह प्रस्ताव रकबा 201.079 हेक्टेयर वनभूमि उपरि सतह उपयोग का नहीं बल्कि भूमिगत कोयला उत्खनन का है अतः यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xvii)	The State Government and user agency shall monitor the mining induced subsidence and take appropriate mitigative measures to ensure that it remains within the permissible limit;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xviii)	The User agency and the State Government shall implement tire Wildlife Conservation Plan for area located within 10 kilometer distance from the forest land proposed to be diverted from the funds to be provided by the user agency;	प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण वन्यप्राणियों पर कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ेगा। अतः मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) से वन्यप्राणी प्रबंधन योजना बनाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
(xix)	The user agency shall implement the following activities under the supervision of the State Forest Department at the project cost;	निम्नानुसार हैः–
(a)	Mitigative measures to minimize soil erosion and choking of stream shall be initiated to be implemented within a period of three years with effect from the date of issue of Stage-II clearance in accordance with the approved Plan in consultation with the State Forest Department;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(b)	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds, in the appropriate area within the mining lease to arrest soil erosion in accordance with the approved scheme;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।

(c)	Construction of check dams, retention /toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour in accordance with the approved scheme;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(d)	Stabilize the overburden dumps by appropriate grading/benching, in accordance with the approved scheme, so as to ensure that angles of repose at any given place is less than 28° ; and	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(e)	No damage shall be caused to the top-soil and the user agency will follow the top soil management plan;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xx)	The User Agency shall undertake mining in a phased manner after taking due care for reclamation of the mined over area. The concurrent reclamation plan as per the approved mining plan shall be executed by the User Agency from the very first year, and an annual report on implementation thereof shall be submitted to the Nodal Officer, Forest (Conservation) Act, 1980, in the concerned State Government and the concerned Regional Office of the Ministry. If it is found from the annual report that the activities indicated in the concurrent reclamation plan are not being executed by the User Agency, the Nodal Officer or the Addl. Pr. Chief Conservator of Forests (Central) may direct that the mining activities shall remain suspended till such time, such reclamation activities area satisfactorily executed;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxi)	The user agency shall implement the R&R Plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।

	before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government/Regional Office of MoEF&CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones;	
(xxii)	The user agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Birds nests artificially made out of eco-friendly material shall be used in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxiii)	The boundary of the diverted forest land, mining lease and safety zone, as applicable, shall be demarcated on ground at the project cost, by erecting four feet high reinforced cement concrete pillars, each inscribed with its serial number, distance from pillar to pillar and GPS co-ordinates;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxiv)	The ground area over the mine shall not be allowed to be used for construction of residential buildings or labour camps;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxv)	The State Government shall ensure that green cover on the ground over the underground part of mine shall be maintained as forest and supplemented by plantations in gaps at the cost of user agency;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxvi)	The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required;	आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्र. J-11015/310/2010-IA.II(M) दिनांक 23/12/2010 की प्रति प्रस्तुत की गई है जो संलग्न है।

(xxvii)	Any tree felling shall be done only when it is unavoidable and that too under strict supervision of the State Forest Department;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxviii)	The layout plan of the proposal shall not be changed without the prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxix)	No labour camp shall be established on the forest land;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxx)	The User Agency shall provide fuels preferably alternate fuels to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forest areas;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxxi)	The State Government and the User agency shall ensure de-silting of the village tanks and other water bodies located within five km from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks/water bodies, whenever required preferably within five years from the date of approval of Stage-II Clearance;	आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्ताव भूमिगत माईनिंग का होने के कारण यह शर्त लागू नहीं होती है।
(xxxii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxxiii)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agency, department or person without prior approval of the Central Government;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxxiv)	No damage to the flora and fauna of the adjoining area shall be caused;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxxv)	The User Agency shall submit the annual self - compliance report in respect of the above stated conditions to the State Government, concerned Regional Office and to this Ministry by the end of March every year;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।

(xxxvi)	Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife; and	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।
(xxxvii)	The user agency shall comply all the provisions of the all Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project;	आवेदक संस्था को शर्त मान्य है। आवेदक संस्था का वचन पत्र संलग्न है।

अतः प्राप्त पालन प्रतिवेदन संलग्न कर प्रकरण में औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

6/5/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ–1/FP/MP/MIN/24598/2017/10-11/1493 भोपाल, दिनांक 06-05-2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) बैतूल वृत्त बैतूल, मध्यप्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, उत्तर बैतूल, मध्य प्रदेश।
3. महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, पाथाखेड़ा क्षेत्र, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

6/5/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Status of the Payment made by User Agencies

Help

Click on **Proposal No.** to view Detail of proposal. Click on **Demand letter** to view Uploaded demand letter.

CA : Compensatory Afforestation; Addl CA : Additional Compensatory Afforestation; PCA : Penal Compensatory Afforestation; CAT : Catchment Area Treatment; Addl PA : Additional Charges for protected area; NPV : Net Present Value;

To be Verified : This icon shows that the details of the Funds submittted by User Agency are yet to be verified by Nodal Officer.

Verified : This icon shows that the demand has been verified by Nodal Officer.

Challan Generated : This icon shows that the challan has been generated.

Unpaid : This icon shows that the payment yet to be made.

Paid : This icon shows that the payment has been made.

◉ **Proposals received on or after 15th July 2014** ○ **All Proposals received upto 14th July 2014**

Select Region : Bhopal **Select State :** Madhya Pradesh

Select User Agency : Select

Online Help/Query

Payment Status : ◉ **Paid** ○ **Unpaid** ○ **All**

Bank Name : --Select All-- **Mode of Payment :** --Select All--

Transaction Date (From) : **Transaction Date (To) :**

Enter value for Search : 24598

SEARCH

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/MP/MIN/24598/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/MP/MIN/24598/2017) Expansion of Tawa-II UG Mine	MIN245982017333	14 May 2018	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 62937727/- , **NIL :** 0/- **Total :** 62937727/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 25 Mar 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 25 Mar 2021 **Transaction Date** : 31 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112512291213GZ1U8Demand.pd Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=MIN245982017333)

SWACHH BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/) Power To Empower (HTTP://WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/) Open Government Data (OGD) Platform India

india.gov.in The national portal of India (HTTPS://INDIA.GOV.IN/)

mygov